अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

मेसर्स ईआरए इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 12627-12628/2017)

12 सितंबर, 2017

[आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996-धारा 11 (6), 12 और 13-मध्यस्थ के रूप में एक पक्ष के कर्मचारी की नियुक्ति-चुनौती-एक ताप विद्युत परियोजना के लिए स्थायी बस्ती के निर्माण कार्य के लिए अपीलकर्ता-ए. पी. सी. पी. एल. और प्रतिवादी-ई. आई. ई. एल. के बीच अनुबंध-पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ-अपीलकर्ता ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी. ई. ओ.) को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया-पक्ष मध्यस्थ के समक्ष पेश हुए-हालांकि, बाद में प्रतिवादी ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन को चुनौती दी-मध्यस्थ द्वारा अस्वीकृत आपत्ति-एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा याचिका-उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा पहले से नियुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति को रद्द कर दिया-अपील पर मध्यस्थ न तो इंजीनियर प्रभारी था और न ही काम का दिन-प्रतिदिन का प्रभारी-नियुक्त मध्यस्थ न तो अनुबंध के संबंध में सौदा करने वाला प्राधिकरण था और न ही सीधे उस अधिकारी (अधिकारियों) के अधीन था जिसका निर्णय विवाद का विषय था-रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में संदेह पैदा कर सके-इस प्रकार, विचाराधीन मध्यस्थ की नियुक्ति को अवैध या अप्रवर्तनीय नहीं कहा जा सकता है-इसके अलावा; प्रतिवादी ने स्वयं मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया और अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के

संदर्भ में कोई चुनौती नहीं दी-धारा 11 (6) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए कार्रवाई का कोई कारण वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं हुआ था-उच्च न्यायालय ने गलती की।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 12-मध्यस्थ की टायर नियुक्ति को चुनौती देने के लिए आधार-2015 के संशोधन अधिनियम से पहले-अपीलार्थी-ए. पी. सी. पी. एल. और प्रतिवादी-ई. आई. ई. एल. के बीच अनुबंध-पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए-अनुबंध के अनुसार, अपीलार्थी ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी. ई. ओ.) को 19.08.2015 पर एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। 2015 का संशोधन लागू होने से पहले-पहले से नियुक्त मध्यस्थ की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए, एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका-धारितः धारा 12 (1) जो 2015 के संशोधन से पहले थी, मध्यस्थ के रूप में संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किए गए व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करने की संभावना वाली किसी भी परिस्थिति का लिखित में खुलासा करने के लिए बाध्य करती है-यह प्रत्यर्थी का मामला नहीं है कि कोई निष्पक्ष और सही खुलासा नहीं किया गया था-इस प्रकार, यह तथ्य कि पहले से नियुक्त मध्यस्थ स्वयं मध्यस्थता समझौते के पक्षों में से एक का कर्मचारी होता हैः संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले ऐसी नियुक्ति को अमान्य और अप्रवर्तनीय बनाता है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 11 (6)-मध्यस्थों की नियुक्ति की योजना-2015 के संशोधन से पहले और बाद में शक्ति का प्रयोग-मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 वर्तमान मामले में, संबंधित परियोजना के परियोजना प्रभारी द्वारा मध्यस्थता के लिए प्रदान किया गया अनुबंध, और यदि ऐसे परियोजना प्रभारी कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक थे, तो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा मध्यस्थता। इसने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान किया कि कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही मध्यस्थ ने उन मामलों को निपटाया हो जिन से अनुबंध उनके कर्तव्यों के दौरान संबंधित था या विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किया था। यह तथ्य कि नामित मध्यस्थ मध्यस्थता समझौते के पक्षों में से किसी एक का कर्मचारी है, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के लागू होने से पहले, इस तरह की नियुक्ति को अमान्य और अप्रवर्तनीय नहीं बना दिया है। संशोधन-पूर्व मामलों में, उत्तर रेलवे प्रशासन में निर्धारित कानून को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें समझौते की शर्तों का यथासंभव पालन किया जाना चाहिए और/या प्रभावी किया जाना चाहिए। [पैरा 16,17 और 21] [512-ई-जी; 523-ई)।

उत्तर रेलवे प्रशासन। रेल मंत्रालय, नई दिल्ली बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (2008) 10 एस. सी. सी. 240: (2008) 12 एस. सी. आर. 216-लागू हुआ।

1.2 धारा 12 (1), मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, जैसा कि 2015 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले था, मध्यस्थ के रूप में संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किए गए व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करने वाली किसी भी परिस्थिति का लिखित रूप में खुलासा करने के लिए बाध्य करता है। वर्तमान मामले में, मध्यस्थ निस्संदेह अपीलार्थी-अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का एक कर्मचारी है, लेकिन जब तक उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में कोई उचित आशंका नहीं है, तब तक नियुक्ति को अमान्य और अप्रवर्तनीय नहीं माना जा सकता है। केवल यह तथ्य कि मध्यस्थ एक कर्मचारी है,

वास्तव में पक्षपात या पक्षपात की किसी भी धारणा को उठाने का आधार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई निष्पक्ष और सही खुलासा नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी-मेसर्स एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अपनी याचिका में केवल इतना ही आरोप लगाया था कि "उसने स्वयं प्रत्यर्थी-कंपनी में अपनी आधिकारिक क्षमता में प्रकृति के अनुबंधों से निपटा है जो विचाराधीन अनुबंध कार्यों के समान हैं।" प्रत्यर्थी ने संशोधन अधिनियम के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए यह भी प्रस्तुत किया था, "कथित रूप से नियुक्त व्यक्ति इसमें प्रत्यर्थी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसकी ऐसी स्थिति के कारण प्रत्यर्थी-कंपनी पर नियंत्रण प्रभाव भी होता है।" उसी समय, उच्च न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ अभियंता प्रभारी या कार्य का दिन-प्रतिदिन प्रभारी नहीं था और वास्तव में, अभियंता प्रभारी ए. जी. एम. (सी. सी. डी.-टाउनशिप) था, जिसके अधीन अन्य इंजीनियरों की एक टीम काम कर रही थी और ए. जी. एम. (सी. सी. डी.-टाउनशिप) ए. जी. एम. (एम. ई.-सी. सी. डी.) को रिपोर्ट करता था, जो बदले में सी. ई. ओ. (ए. पी. सी. पी. एल.) यानी मध्यस्थ को रिपोर्ट करता था। अभिलेख पर तथ्य और पदानुक्रम यह नहीं दर्शाते हैं कि वर्तमान मामले में मध्यस्थ या तो अनुबंध के संबंध में व्यवहार प्राधिकरण था या सीधे अधिकारी (ओं) के अधीन था जिसका निर्णय विवाद का विषय है। वास्तव में, निर्णय, जो विवाद का विषय हो सकता है, उसके अधीनस्थों का था। हो सकता है कि उसने विचाराधीन अनुबंध कार्यों के समान प्रकृति के अनुबंधों से निपटा हो, लेकिन दस्तावेज़ अपने आप में नियुक्ति को अमान्य नहीं करते हैं। चूंकि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामित मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा कर सके, इसलिए मध्यस्थ की नियुक्ति को किसी भी तरह से अवैध या अप्रवर्तनीय नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 191 (514-डी-एच; 515-ए-सी)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (2009) 8 एस. सी. सी. 520: [2009! 13 एस. सी. आर. 510-पर निर्भर था।

1.3 उभरने वाले सिद्धांत इस प्रकार हैंः -

ए. 1996 अधिनियम द्वारा शासित मामलों में यह संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले थाः -

(i) यह तथ्य कि नामित मध्यस्थ किसी एक पक्ष का कर्मचारी है, वास्तव में उसकी ओर से पक्षपात या पक्षपात या स्वतंत्रता की कमी का अनुमान लगाने का आधार नहीं है। तथापि, एक कर्मचारी मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में एक न्यायोचित आशंका हो सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति विषय अनुबंध के संबंध में नियंत्रण या व्यवहार करने वाला प्राधिकारी था या यदि वह उस अधिकारी के सीधे अधीनस्थ है जिसका निर्णय विवाद का विषय है।

(ii) जब तक 1996 अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत अधिकारिता का आह्वान करने के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं होता है, तब तक मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करने का कोई सवाल ही नहीं है।

(iii) मुख्य न्यायाधीश या उसका नामित सदस्य धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थता खंड में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास करेगा।

(iv) धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय, यदि परिस्थितियां मौजूद हैं, नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हैं, या यदि अन्य परिस्थितियां निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता होती हैं, तो मुख्य

न्यायाधीश या उनका नामित, दर्ज किए जाने वाले कारणों से नामित मध्यस्थ की अनदेखी कर सकता है और किसी और को नियुक्त कर सकता है।

बी. संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद 1996 अधिनियम द्वारा शासित मामलों में: -

यदि मध्यस्थता के कारण संशोधित प्रावधानों में गड़बड़ी पाई जाती है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति, भले ही स्पष्ट रूप से समझौते में मध्यस्थता खंड के अनुरूप हो, अवैध होगी और इस प्रकार न्यायालय ऐसे मध्यस्थ (ओं) को नियुक्त करने की अपनी शक्तियों के भीतर होगा जो अनुमेय हो। (पैरा 22) (523-जी-एच; 524-ए-एफ)।

1.4 अपरिवर्तित धारा 12 में निर्धारित प्रक्रिया में मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करने की संभावना वाली परिस्थितियों का प्रकटीकरण अनिवार्य है। प्रत्यर्थी का यह मामला नहीं है कि धारा 12 के प्रावधानों का बिना संशोधन के किसी भी रूप में उल्लंघन किया गया है। किसी भी मामले में प्रावधान में स्पष्ट और सटीक प्रक्रिया पर विचार किया गया जिसके तहत मध्यस्थ को चुनौती दी जा सकती है और धारा 13 के तहत उस ओर से आपत्तियों को निर्धारित समय के भीतर और उसमें विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार उठाया जा सकता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि समय के भीतर और निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में ऐसी कोई चुनौती नहीं उठाई गई थी। वास्तव में, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता में भाग लिया था और अपने दिनांक 04.12.2015 के संचार द्वारा अपने दावे का बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी और उसे मध्यस्थता की प्रक्रिया और प्रगति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। मध्यस्थता, 19.08.2015 पर मध्यस्थ

की नियुक्ति के अनुसरण में, कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी। [पैरा 23,24] [524-एच; 525-ए-सी]।

वायस्टाल्पाइन शियनन जी. एम. बी. एच. बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2017) 4 एस. सी. सी. 665-विशिष्ट।

एसीई पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स (पी) लिमिटेड 'भारत पेटलियम कार्पोरेशन। लिमिटेड (2007) 5 एस. सी. सी. 304: (2007] 4 एस. सी. आर. 777; भारत संघ बनाम भारत बैलेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (पी) लिमिटेड (2007) 7 एस. सी. सी. 684: (2007) 8 एस. सी. आर. 993; भारत संघ वी. सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (2009) 4 धारा 523: (2009) 3 एस. सी. आर. 563: डेने/(स्वामित्व) लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक अन्य (2010) 6 एस. सी. सी. 394: [20 आई. ओ.] 6 एस. सी. आर. 784: दातार स्विचगियर्स लिमिटेड बनाम टाटा फाइनेंस लिमिटेड (2000) 8 एस. सी. सी. 151; भूपिंदर सिंह बिंद्रा बनाम भारत संघ (1995) 5 एस. सी. सी. 329: एस. सी. आर. 417; डेने/(प्रोपराइटरी) लिमिटेड बनाम मंत्रालय ए/रक्षा (2012) 2 एस. सी. सी. 759: (2012) 2 एस. सी. आर. 897: भारत संघ और अन्य बनाम वियार प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2015) 2 एस. सी. सी. 52; ट्रिपल इंग। वर्क्स बनाम उत्तर पूर्वी रेलवे और अन्य। (2014) 9 एस. सी. सी. 288: (2014) 6 एस. सी. आर. 1143-संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2009]13 एससीआर 510	विश्वास किया	पैरा 20
[2008]12 एससीआर 216	लागू किया	पैरा 20
[2007]4 एससीआर 777	संदर्भित	पैरा 20
[2009]3 एससीआर 993	संदर्भित	पैरा 20

[2010]6 एससीआर 784	संदर्भित	पैरा 20
[2000]8 एससीसी 151	संदर्भित	पैरा 20
[1995]2 पूरक एससीआर 417	संदर्भित	पैरा 20
[2012]2 एससीआर 897	संदर्भित	पैरा 20
[2015]2 एससीसी 52	संदर्भित	पैरा 20
[2014]6 एससीआर 1143	संदर्भित	पैरा 20
[2017]4 एससीसी 665	विशिष्ट	पैरा 20

सिविल अपीलीय अधिकारिता :सिविल अपील संख्या 12627-12628/2017

ओ. एम. पी. में (टी) (कॉम.) नं. 13/2016 और एआरबी. पी. संख्या 136/2016 नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 29.07.2016 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 12629-12630/2017

उपस्थित पक्षों की ओर से विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत संगल, सुश्री वर्मिका तोमर, सुश्री दीपिका कालिया, सुश्री विदुशी गर्ग, मनोज के. सिंह, प्रेम प्रकाश, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय उदय उमेश ललित, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई। ये अपीलें ओएमपी (टी) (कॉम) संख्या 13/2016 और मध्यस्थता याचिका संख्या 136/2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित 29.07.2016 के न्यायिक निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं।

2. हरियाणा के झज्जर में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए स्थायी टाउनशिप का निर्माण कार्य प्रत्यर्थी-मेसर्स एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को 20.05.2009 पर दिया गया था और अनुबंध दिनांक 17.11.2009 पर दिया गया था। जी. सी. सी. के खंड 56 ने निम्नलिखित शर्तों में पक्षों के बीच मध्यस्थता निर्धारित कीः

"56. मध्यस्थता:

सिवाय इसके कि जहां अनुबंध में अन्यथा प्रावधान किया गया है, पहले उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइनों, चित्रों और निर्देशों के अर्थ से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद और काम पर उपयोग की जाने वाली कारीगरी या सामग्री की गुणवत्ता के बारे में या किसी अन्य प्रश्न, दावा, अधिकार, विषय या चीज के बारे में जो भी अनुबंध से या उससे संबंधित किसी भी तरह से उत्पन्न होते हैं. डिजाइन, ड्राइंग, विनिर्देश, अनुमान, निर्देश, आदेश या अन्यथा कार्यों से संबंधित इन शर्तों, या कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने या छोड़ने के बाद उत्पन्न होने वाले निष्पादन या विफलताओं को मालिक के संबंधित परियोजना प्रभारी के एकमात्र मध्यस्थता को भेजा जाएगा, और यदि परियोजना प्रभारी कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, तो एकमात्र व्यक्ति को भेजा जाएगा। यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ एनटीपीसी लिमिटेड (पूर्व में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड) का कर्मचारी है, और उसे उन मामलों से निपटना था जिनसे अनुबंध संबंधित है और अपने कर्तव्यों के दौरान उसने विवादों या मतभेदों के सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए थे, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस मध्यस्थ को मामला मूल रूप से स्थानांतरित करने या

अपना कार्यालय खाली करने के लिए संदर्भित किया गया है या इस तरह के हस्तांतरण, पद की छुट्टियों या कार्य करने में असमर्थता के समय उपरोक्त किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने के कारण, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (पूर्व में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड), अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगा।

3. अपीलार्थी-अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार, काम पूरा करने की निर्धारित तिथि 19.05.2011 थी, लेकिन काम की प्रगति काफी धीमी थी, जिसने अपीलार्थी को अपने दिनांक 18.07.2014,24 के पत्रों द्वारा कुछ शेष कार्यों को रद्द करने के लिए मजबूर किया। 10.2014,30.06.2015 और 08.07.2015। आई. डी. 1 दिनांकित अपने पत्र द्वारा प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया कि परियोजना में देरी प्रत्यर्थी के कारण नहीं थी और कुछ शिकायतों को निर्धारित करने के बाद, पत्र ने इसके बाद मध्यस्थता का आह्वान करने की मांग की, जिसमें आगे कहा गया कि मध्यस्थता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से हो, पत्र का प्रासंगिक हिस्सा हैः -

"उपरोक्त परिस्थितियों और हमारे दावों/भुगतानों के निपटारे की दिशा में एपीसीपीएल की निष्क्रियता को देखते हुए, हम अनुबंध समझौते के मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अनुबंध समझौते के जीसीसी के खंड 56 के अनुसार हमारे दावों के निपटारे के लिए मध्यस्थ नियुक्त करें।

हालांकि, हम आपका ध्यान इस कानूनी बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि एक बार मालिक/नियोक्ता के उच्चतम स्तर पर आंशिक रूप से रद्द करने का

आदेश पारित हो जाने के बाद, उक्त प्राधिकरण और विशेष रूप से उसके अधीनस्थ द्वारा गठित विवाद के समाधान के लिए किसी भी मंच का कोई कानूनी परिणाम नहीं है। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि कोई भी अपने स्वयं के मामले में न्याय नहीं कर सकता है। इसलिए, कानून की उपरोक्त स्थिर स्थिति के आलोक में, हम माननीय उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश के माध्यम से एक स्वतंत्र मध्यस्थता की मांग करते हैं, ताकि पूर्वगामी पैरा में उल्लिखित हमारी शिकायत का समर्थन किया जा सके। चूंकि यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि हमें स्वतंत्र मध्यस्थों का एक पैनल उपलब्ध कराया जाए ताकि हम पैनल में से चुन सकें। हम एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए भी सहमत होंगे जिसमें आपकी कंपनी के नामित व्यक्ति शामिल होंगे। हमारे नामित और दोनों नामित मध्यस्थ जो पीठासीन/अंपायर मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं। हम अनुरोध करते हैं कि इस संबंध में कानून के अनुसार जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।

4. जवाब में, जवाब के तहत पत्र में आरोपों का खंडन करते हुए, अपीलार्थी ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 19.08.2015 पर एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े और उसी दिन प्रतिवादी को निम्नलिखित शर्तों में सूचित कियाः

> "कृपया ध्यान दें कि जी. सी. सी. के मध्यस्थता खंड 56 के संदर्भ में हमारे द्वारा प्रस्तावित मध्यस्थों के किसी भी पैनल से मध्यस्थ के चयन के लिए आपके द्वारा कोई प्रावधान नहीं है। आपके द्वारा सुझाए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन का भी कोई प्रावधान नहीं है। जी. सी. सी. के खंड 56 में मध्यस्थ के रूप में नामित अधिकारियों की नियुक्ति की परिकल्पना की गई है और

तदनुसार आपके अनुरोध पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. पी. सी. पी. एल. को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया है। विद्वान मध्यस्थ आपको समय पर मध्यस्थता कार्यवाही के बारे में सूचित करेगा।"

26.09.2015 दिनांकित आगे के संचार द्वारा अपीलार्थी ने 19.08.2015 दिनांकित पत्र में अपना रुख दोहराया।

5. इस बीच, इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ ने मध्यस्थता में पहली सुनवाई 07.10.2015 पर निर्धारित की। पक्षकार 7.10.2015 पर उपस्थित हुए और कार्यवाही से पता चलता है कि सुनवाई 09.04.2016 पर तय की गई थी, जिस समय तक जवाबी दावे आदि के जवाब का बयान दाखिल करना पूरा होना था। कार्यवाहियों से यह नहीं पता चलता कि मध्यस्थता कार्यवाहियों को जारी रखने के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा कोई आपत्ति उठाई गई है। 04.12.2015 पर प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थ को एक पत्र संबोधित किया गया था जिसमें अपने दावे का बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। यह कहा गया था, अन्य बातों के साथः

"07.10.2015 पर आयोजित अंतिम सुनवाई में दावेदार को अपना दावा विवरण दाखिल करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया था। इस संबंध में यह बताना है कि हमें दावे का विवरण देने के लिए अपने अन्य कार्यालयों से कुछ और डेटा और फाइलें एकत्र करने की आवश्यकता है। उस उद्देश्य के लिए, हमें अपने दावे का विवरण प्रस्तुत करने के लिए लगभग एक महीने का और समय चाहिए।

अत: अनुरोध है कि एल.डी. एकमात्र मध्यस्थ कृपया दावेदार को अपना दावा विवरण दाखिल करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दे सकता है।"

अभिलेख के अनुसार. मध्यस्थ को एक महीने का समय दिया, जैसा कि प्रार्थना की गई थी।

6. मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (जिसे इसके बाद "संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को राजपत्रित किया गया था और धारा 1 (2) के अनुसार, संशोधन अधिनियम को 23 अक्टूबर, 2015 को लागू माना गया था।

7. पहली बार 12.01.2016 पर, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थ को चुनौती देने की मांग की और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में निम्नानुसार आपत्ति जताईः

"हमारे द्वारा संबोधित उपरोक्त संदर्भित संचारों के संदर्भ में, हम एतद्द्वारा कहते हैं कि वर्तमान मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन पूरी तरह से अमान्य/अमान्य है और कानून के तय किए गए सिद्धांतों के खिलाफ है, और जिसके कारण एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड एक स्वतंत्र मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क करके उचित कानूनी उपचार की मांग कर रहा है। तदनुसार, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने आप को संदर्भ ग्रहण करने और वर्तमान कथित कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने से रोकें, जब तक कि उपरोक्त संदर्भित कानूनी कार्यवाही का अंतिम परिणाम, जिसे एरा एनफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा तुरंत और तत्काल दायर/प्राथमिकता दी जानी चाहिए। "

8. मध्यस्थ द्वारा 22.01.2016 पर आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादी ने बिना कोई विरोध उठाए 07.10.2015 पर मध्यस्थता

कार्यवाही में भाग लिया था। इसके बाद प्रत्यर्थी को 16.02.2016 पर आयोजित होने वाली मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सूचित किया गया था। हालाँकि, प्रतिवादी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 1996 अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 14 के तहत याचिका दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने के लिए ओ. एम. पी. (टी.) (कम) संख्या 13/2016 के रूप में पंजीकृत है। याचिका में उठाए गए आधार I, IV, VI, VII और VIII थेः -

I यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, समझौते का एक पक्ष अपने उद्देश्य में मध्यस्थ नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्याय और समानता के हित के लिए आवश्यक है कि जहां अनुबंध का कोई पक्ष शर्त के किसी भी उल्लंघन को करने का विवाद करता है, तो निर्णय एक स्वतंत्र व्यक्ति या निकाय द्वारा किया जाना चाहिए न कि अनुबंध के दूसरे पक्ष द्वारा।

IV उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि कथित रूप से नियुक्त मध्यस्थ, श्री एस.के. सिन्हा, अन्यथा एक स्वतंत्र मध्यस्थ के कार्यों को करने में भी असमर्थ होंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं, प्रतिवादी-कंपनी में अपनी आधिकारिक क्षमता में, यहां प्रश्न में अनुबंध कार्यों के समान प्रकृति के अनुबंधों को निपटाया है (जिसमें शामिल हैं) वर्तमान अनुबंध कार्य), प्रतिवादी-कंपनी की ओर से।

VI यह भी उल्लेखनीय होगा कि माननीय न्यायालयों ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है और कहा है कि सरकारी सांविधिक प्राधिकरणों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कर्मचारी मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए प्रावधान/नियुक्ति करने की नीति एक परेशान करने वाली समस्या है जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जो एक स्वतंत्र

और निष्पक्ष मध्यस्थ की आवश्यकता को दोहराते हुए नए अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के सम्मान में अधिक है।

VII यह कि उपरोक्त भावना को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि माननीय न्यायालयों द्वारा दोहराया गया है, अधिनियम को विधानमंडल द्वारा भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है, जिसके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि एक मध्यस्थ जो एक कर्मचारी, प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधन का हिस्सा है या जिसका मध्यस्थता के किसी एक पक्ष में समान नियंत्रण प्रभाव है, एक वैध आधार है जो एक मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म देता है। इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया है कि मामले/विषय वस्तु में एक मध्यस्थ की पिछली भागीदारी भी एक वैध आधार होगी जो एक मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के रूप में उचित संदेह को जन्म देगी।

VIII यह कि वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रत्यर्थी द्वारा इस प्रकार नियुक्त कथित मध्यस्थ स्वयं प्रत्यर्थी का कर्मचारी है। वास्तव में, कथित रूप से नियुक्त व्यक्ति प्रतिवादी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी. ई. ओ.) होता है, जो इस तरह की स्थिति के कारण प्रतिवादी-कंपनी पर भी नियंत्रित प्रभाव रखता है, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता यहां अपने दावों का दावा करना चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में, कथित रूप से नियुक्त मध्यस्थ कानूनी और वास्तव में स्वतंत्र या निष्पक्ष तरीके से मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यों को करने में असमर्थ होगा।

9. उसी दिन, पक्षकारों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए 1996 अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत प्रत्यर्थी द्वारा एक अन्य याचिका मध्यस्थता याचिका संख्या 136/2016 दायर की गई थी। जैसा कि उक्त याचिका में कहा गया है, कार्रवाई का कारण थाः -

"कि वर्तमान याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण विभिन्न तिथियों पर उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी को लंबे समय से बकाया भुगतान जारी करने के लिए अनुरोध किया गया था। कार्रवाई का कारण आगे 29.07.2015 पर उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता का आह्वान किया गया था। कार्रवाई का कारण तब और बढ़ गया, जब प्रतिवादी ने एक स्वतंत्र मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को गलती से और अवैध रूप से खारिज कर दिया, जो कार्रवाई का कारण अभी भी मौजूद है और जारी है क्योंकि प्रतिवादी बकाया भुगतान करने और एक स्वतंत्र मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त करने में विफल रहा है।"

10. 01.03.2016 पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और मध्यस्थता में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अपीलार्थी द्वारा इस मामले को चुनौती देते हुए कहा गया था कि 1996 अधिनियम की धारा 14 के तहत याचिका विचारणीय नहीं थी; कि मध्यस्थ को जी. सी. सी. के खंड 56 के संदर्भ में सख्ती से नियुक्त किया गया था; और हालांकि प्रत्यर्थी को 19.08.2015 पर मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन नियुक्ति को चुनौती देने के लिए कोई कदम निर्दिष्ट समय के भीतर और 1996 अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से नहीं उठाए गए थे।

11. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और अपील के तहत आदेश द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को रद्द कर दिया और अपीलार्थी को विभिन्न विभागों से तीन-पैनल मध्यस्थों के नाम प्रतिवादी को सुझाने का निर्देश दिया जो बाद में उनमें से किसी एक को मामले में मध्यस्थ के रूप में चुन सकते थे। यह निर्देश दिया गया था कि अपीलार्थी द्वारा विफल होने की स्थिति में, प्रत्यर्थी याचिकाओं को फिर से शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, इस मामले में न्यायालय दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र

द्वारा रखी गई सूची से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगा। यह भी देखा गया कि मध्यस्थ अपीलार्थी का सी. ई. ओ. था और पहले वर्तमान मामले में शामिल मामलों/अनुबंध कार्यों में शामिल था और इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि आंशिक रूप से रद्द करने के निर्णय अपीलार्थी के उच्चतम स्तर पर लिए गए थे। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा व्यक्त की गई आशंका उचित थी और अस्पष्ट या सामान्य आपत्ति नहीं थी। उच्च न्यायालय की टिप्पणियां इस प्रकार थीं: -

> "13. मध्यस्थ, हालांकि प्रतिवादी-कंपनी के सी. ई. ओ. और इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के परियोजना प्रभारी, पी. ओ. झरी, जिला। झज्जर, हरियाणा, इंजीनियर प्रभारी या काम का दिन-प्रतिदिन का प्रभारी नहीं था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन अनुबंध के तहत किया जाना था। वास्तव में, इस परियोजना के लिए प्रभारी अभियंता ए. जी. एम. (सी. सी. डी.-टाउनशिप) हैं जो इंजीनियरों के समूह (डिप्टी इंजीनियर) द्वारा समर्थित हैं। प्रबंधक, प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक) कार्य के निष्पादन के लिए उनके अधीन काम कर रहे हैं। इसके अलावा, ए. जी. एम. (सी. सी. डी.-टाउनशिप) ए. जी. एम. (एम. ई./सी. सी. डी.) को रिपोर्ट करता है जो बदले में सी. ई. ओ. (ए. पी. सी. पी. एल.) को रिपोर्ट करता है।
>
> 37. यह आम बोलचाल है जो अक्सर उद्धृत की जाती है "न केवल न्याय किया जाना चाहिए" इसे किया जाता हुआ भी देखा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि नियम नैतिक निर्माण हैं जो उच्च मूल्य प्रदान करने के लिए होते हैं। 2015 के संशोधन में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी प्रकार के किसी भी संबंध या हित के

अस्तित्व से उचित संदेह पैदा होने की संभावना है क्योंकि उसकी तटस्थता से बचा जाना चाहिए या किसी भी कर्मचारी, प्रबंधक, निदेशक, या जिसका अतीत या वर्तमान व्यवसाय है या जिसका नियंत्रण प्रभाव है, विवाद के किसी पक्ष के साथ संबंध को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह, संशोधित अधिनियम 2015 (2016 का 3) की पांचवीं अनुसूची में यह उचित रूप से अनिवार्य है कि यदि पिछले तीन वर्षों के भीतर मध्यस्थ को एक पक्ष द्वारा दो या अधिक अवसरों पर नियुक्त किया गया है और मध्यस्थ ने तीन वर्षों के भीतर एक पक्ष से जुड़े संबंधित मुद्दे पर दूसरे मध्यस्थता में कार्य किया है, तो उसकी नियुक्ति मध्यस्थों की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आह्वान संशोधन से लगभग तीन महीने पहले किया गया था। लेकिन न्यायालय को अधिनियम के उद्देश्य और दायरे के बारे में ध्यान रखना होगा।

38. वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आह्वान गैर-संशोधित अधिनियम के आधार पर था, लेकिन फिर भी अधिनियम की व्यापक धारा 12 इसी तरह का संकेत देगी। प्रत्यर्थी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ प्रत्यर्थी कंपनी का सी. ई. ओ. और कार्यकारी होता है जो उसी कार्यालय/विभाग से भी होता है। तटस्थता बनाए रखने के लिए या याचिकाकर्ता के मन में किसी भी संदेह और याचिका में दिए गए कारणों से बचने के लिए, यह उचित होगा कि स्वतंत्र एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाए क्योंकि अंततः तटस्थ व्यक्ति को केवल पक्षों के बीच विवाद का फैसला करना है। यहां तक कि अधिनियम का

उद्देश्य और दायरा भी ऐसा कहता है कि मध्यस्थता प्रक्रिया निष्पक्ष और आधारहीन होनी चाहिए। इस प्रकार, प्रत्यर्थी कंपनी के सी. ई. ओ. श्री एस. के. सिन्हा की नियुक्ति समाप्त कर दी जाती है और एक बार मध्यस्थ की नियुक्ति समाप्त हो जाने के बाद, न्यायालय याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार कर सकता है।"

12. उच्च न्यायालय के निर्णय को अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई है और श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि मध्यस्थ की नियुक्ति पूरी तरह से जी. सी. सी. के खंड 56 के अनुरूप थी, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए किसी भी शक्ति या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं था और 1996 के अधिनियम में मध्यस्थ को चुनौती देने के लिए स्पष्ट और निश्चित प्रक्रिया पर विचार किया गया था, और भले ही ऐसी चुनौती विफल हो जाए, धारा 13 के तहत उपाय विशिष्ट और अलग प्रकृति का था। दोनों ही मामलों में, उनके अनुसार, प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकता था और दोनों याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

13. जिस हद तक उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अपने मध्यस्थों के पैनल से तीन नाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसमें से प्रत्यर्थी को एकमात्र मध्यस्थ का चयन करना था, प्रत्यर्थी ने 2017 की एसएलपी (सिविल) संख्या 503-504 दाखिल करके फैसले के उस हिस्से को चुनौती दी। प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए, श्री मनोज के सिंह, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के कुछ फैसलों पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि एक अधिकारी जो या तो परियोजना से निपटता है या सीधे प्राधिकरण के अधीनस्थ है, जिसका निर्णय विवाद का विषय था, वह मामले में मध्यस्थ नहीं हो सकता है।

14. शुरुआत में, यह कहा जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता का आह्वान 29.07.2015 पर था, मध्यस्थ को 19.08.2015 पर नियुक्त किया गया था और पक्षकार 07.10.2015 पर मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हुए, 23.10.2015 से बहुत पहले यानी उस तारीख को जब संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। इसलिए वर्तमान विवाद को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान वे हैं जो संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले लागू थे। हमें यहां यह उल्लेख करना चाहिए कि दोनों पक्षों ने इस आधार पर अपनी दलीलों को संबोधित किया है।

15. वर्तमान विवाद पर विचार करने से पहले, हम 1996 के अधिनियम की धारा 12,13 और 14 को उद्धृत कर सकते हैं, जैसा कि वे संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले थेः

"12. चुनौती के लिए आधार.-

(1) जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तो वह लिखित रूप में किसी भी परिस्थिति का खुलासा करेगा जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा होने की संभावना है।

(2) एक मध्यस्थ, अपनी नियुक्ति के समय से और मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, बिना किसी देरी के, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति का पक्षकारों को लिखित रूप में खुलासा करेगा, जब तक कि उनके द्वारा उन्हें पहले ही सूचित नहीं किया गया हो।

(3) एक मध्यस्थ को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब -

(क) ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हैं, या

(ख) उसके पास पार्टियों द्वारा सहमत योग्यताएँ नहीं हैं।

(4) एक पक्ष अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को चुनौती दे सकता है, या जिसकी नियुक्ति में उसने भाग लिया है, केवल उन्हीं कारणों से जिसके लिए वह नियुक्ति के बाद जागरूक हो जाता है।

13. चुनौती प्रक्रिया -

(1) उप-धारा (4) के अधीन, पक्षकार एक मध्यस्थ को चुनौती देने की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर, एक पक्ष जो एक मध्यस्थ को चुनौती देने का इरादा रखता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बारे में जागरूक होने के पंद्रह दिनों के भीतर या धारा 12 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति से अवगत होने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को चुनौती देने के कारणों का एक लिखित विवरण भेजेगा।

(3) जब तक उप-धारा (2) के तहत चुनौती दिया गया मध्यस्थ अपने पद से हट नहीं जाता है या दूसरा पक्ष चुनौती के लिए सहमत नहीं होता है, तब तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण चुनौती पर फैसला करेगा।

(4) यदि पक्षकारों द्वारा सहमत किसी प्रक्रिया के तहत या उप-धारा (2) के तहत प्रक्रिया के तहत कोई चुनौती सफल नहीं होती है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखेगा और मध्यस्थता पुरस्कार देगा।

(5) जहां उप-धारा (4) के तहत एक मध्यस्थता पुरस्कार दिया जाता है, मध्यस्थ को चुनौती देने वाला पक्ष धारा 34 के अनुसार ऐसे मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(6) जहां उप-धारा (5) के तहत किए गए आवेदन पर मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखा जाता है, वहां न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि जिस मध्यस्थ को चुनौती दी गई है वह किसी भी शुल्क का हकदार है या नहीं।

14. कार्य करने में विफलता या असंभवता

(1) मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाएगा यदि -

(क) वह न्यायिक रूप से या वास्तविक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है या अन्य कारणों से अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है; और

(ख) वह अपने पद से हट जाता है या पक्ष उनके जनादेश की समाप्ति के लिए सहमत होते हैं।

(2) यदि उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी आधार के संबंध में कोई विवाद बना रहता है, तो कोई पक्षकार, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो जाए, जनादेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

(3) यदि, इस धारा या धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत, कोई मध्यस्थ अपने पद से हट जाता है या कोई पक्ष मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने के लिए सहमत होता है, तो इसका अर्थ इस धारा

या धारा 12 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी आधार की वैधता की स्वीकृति नहीं होगी।"

16. वर्तमान मामले में जी. सी. सी. के खंड 56 में संबंधित परियोजना के परियोजना प्रभारी द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान है, और यदि ऐसे परियोजना प्रभारी कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं, तो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान है। यह अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रदान करता है कि कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही मध्यस्थ ने उन मामलों को निपटाया हो जिन से अनुबंध अपने कर्तव्यों के दौरान संबंधित था या विवाद या मतभेद में सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किया था।

17. यह तथ्य कि नामित मध्यस्थ मध्यस्थता समझौते के पक्षों में से किसी एक का कर्मचारी होता है, संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले, इस तरह की नियुक्ति को अमान्य और अप्रवर्तनीय नहीं बनाता है। पैराग्राफ 28,30,31 और 32 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम राजू ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय की टिप्पणियां काफी स्पष्ट हैं। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार थेः

"28. प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि नए अधिनियम में एक मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर जोर देने और प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, कोई भी मध्यस्थता समझौता इस हद तक अमान्य और अप्रवर्तनीय होगा कि वह किसी एक पक्ष के अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में नामित करता है।

30. हमें नए अधिनियम के तहत मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले सरकारी/सांविधिक निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (जो अनुबंध का एक पक्ष है) के कर्मचारी के लिए मध्यस्थता समझौते के लिए कोई बाधा नहीं मिलती है। अधिनियम की धारा 11 (8) में मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति से मध्यस्थ की नियुक्ति में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखने की अपेक्षा की गई हैः

"11 (8) (क) पक्षकारों के समझौते द्वारा मध्यस्थ के लिए आवश्यक कोई योग्यता; और

(ख) अन्य विचार जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने की संभावना रखते हैं।

31. धारा 12 (1) एक मध्यस्थ से अपेक्षा करती है कि जब उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाए, तो वह अपनी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करने वाली किसी भी परिस्थिति का लिखित रूप में खुलासा करे। धारा 12 (3) मध्यस्थ को चुनौती देने में सक्षम बनाती है यदि -

(i) परिस्थितियाँ उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हैं, या

(ii) उसके पास पार्टियों द्वारा सहमत योग्यताएँ नहीं हैं।

32. धारा 18 में मध्यस्थ से पक्षकारों के साथ समानता का व्यवहार करने (यानी बिना पक्षपात के) और प्रत्येक पक्ष को अपना मामला पेश करने का पूरा अवसर देने की अपेक्षा की गई है। अधिनियम की धारा 11,12,18 या अन्य प्रावधानों में कुछ भी नहीं बताता है कि

मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थ का नाम रखने वाला कोई भी प्रावधान अमान्य होगा यदि ऐसा नामित मध्यस्थ मध्यस्थता समझौते के किसी एक पक्ष का कर्मचारी है।"

18. इसी निर्णय में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 34 और 35 में एक कर्मचारी मध्यस्थ की 'स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित आशंका' पर निम्नलिखित शब्दों में विचार कियाः -

"34. यह तथ्य कि नामित मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी एक का कर्मचारी है, वास्तव में उसकी ओर से पक्षपात या पक्षपात या स्वतंत्रता की कमी की धारणा को उठाने का आधार नहीं है। तथापि, एक कर्मचारी मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में एक न्यायोचित आशंका हो सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति विषय अनुबंध के संबंध में नियंत्रण या व्यवहार करने वाला प्राधिकारी था या यदि वह उस अधिकारी का प्रत्यक्ष अधीनस्थ है (जैसा कि किसी अन्य विभाग में निम्न श्रेणी के अधिकारी के विपरीत) जिसका निर्णय विवाद का विषय है।

35. यद्यपि नामित मध्यस्थ, यद्यपि सरकार/वैधानिक निकाय/सरकारी कंपनी का एक वरिष्ठ अधिकारी था, का विषय अनुबंध के निष्पादन से कोई लेना-देना नहीं था, तो किसी विशिष्ट साक्ष्य के अभाव में किसी के लिए भी उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर संदेह करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। इसलिए, किसी सरकारी/वैधानिक निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वरिष्ठ अधिकारी (आमतौर पर विभाग के प्रमुख या समकक्ष), जो अनुबंध से जुड़े नहीं

हैं, उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता है और उन्हें केवल इसलिए मध्यस्थ के रूप में काम करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका नियोक्ता अनुबंध का एक पक्ष है।"

19. धारा 12 (1), जो उस समय संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले थी, मध्यस्थ के रूप में संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किए गए व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करने वाली किसी भी परिस्थिति का लिखित रूप में खुलासा करने के लिए बाध्य करती है। वर्तमान मामले में, मध्यस्थ निस्संदेह अपीलार्थी का एक कर्मचारी है, लेकिन जब तक उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में कोई उचित आशंका नहीं है, तब तक नियुक्ति को अमान्य और अप्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, (ऊपर) केवल यह तथ्य कि मध्यस्थ एक कर्मचारी है, वास्तव में पक्षपात या पक्षपात की किसी भी धारणा को उठाने का आधार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई निष्पक्ष और सही खुलासा नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी ने मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने की मांग करने वाली अपनी याचिका में केवल इतना ही आरोप लगाया था, "... उसने स्वयं प्रत्यर्थी-कंपनी में अपनी आधिकारिक क्षमता में प्रकृति के अनुबंधों से निपटा है जो विचाराधीन अनुबंध कार्यों के समान हैं।" प्रत्यर्थी ने संशोधन अधिनियम के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए यह भी प्रस्तुत किया था, ". कथित रूप से नियुक्त व्यक्ति इसमें प्रत्यर्थी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसकी ऐसी स्थिति के कारण प्रत्यर्थी-कंपनी पर नियंत्रण प्रभाव भी होता है।" उसी समय, उच्च न्यायालय ने अपील के तहत निर्णय के पैराग्राफ 13 में कहा कि मध्यस्थ अभियंता प्रभारी या काम का दिन-प्रतिदिन प्रभारी नहीं था और वास्तव में, अभियंता प्रभारी एजीएम (सीसीडी-टाउनशिप) था, जिसके अधीन अन्य इंजीनियरों की एक टीम काम कर रही थी और एजीएम (सीसीडी-टाउनशिप) एजीएम (एमई-सीसीडी) को रिपोर्ट करता था,

जो बदले में सीईओ (एपीसीपीएल) यानी मध्यस्थ को रिपोर्ट करता था। अभिलेख पर तथ्य और जैसा कि उल्लिखित पदानुक्रम से यह नहीं पता चलता है कि वर्तमान मामले में मध्यस्थ या तो अनुबंध के संबंध में व्यवहार प्राधिकरण था या सीधे उस अधिकारी (अधिकारियों) के अधीन था जिसका निर्णय विवाद का विषय है। वास्तव में, निर्णय, जो विवाद का विषय हो सकता है, उसके अधीनस्थों का था। हो सकता है कि उसने अनुबंध कार्यों के समान प्रकृति के अनुबंधों से निपटा हो, लेकिन यह अपने आप में नियुक्ति को अमान्य नहीं करता है। चूंकि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामित मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा कर सके, इसलिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में मध्यस्थ की नियुक्ति को किसी भी तरह से अवैध या अप्रवर्तनीय नहीं कहा जा सकता है।

20. हालाँकि, इस न्यायालय के कई फैसलों पर प्रत्यर्थी ने अपनी इस दलील के समर्थन में भरोसा किया कि वर्तमान मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। इसलिए हम उन निर्णयों से निपट सकते हैं।

ए. उत्तर रेलवे प्रशासन, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में, इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ को एसीई पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (पी) लिमिटेड में इस न्यायालय के दो फैसलों के बीच स्पष्ट संघर्ष पर विचार करने के लिए कहा गया था। पैराग्राफ 5 में उद्धृत अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन था -

> "5 ..... .इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विकल्प का सहारा लेने से पहले, सहमत प्रक्रिया को समाप्त करना होगा। समझौते

को प्रभावी बनाना होगा और अनुबंध का यथासंभव बारीकी से पालन करना होगा। सुधारात्मक उपाय पहले किए जाने चाहिए और न्यायालय अंतिम उपाय है।

निर्णय के पैराग्राफ 12,13 और 14 में चर्चा इस प्रकार थीः -

"12. धारा 11 की योजना को केवल पढ़ने से पता चलता है कि समझौते की शर्तों का पालन करने और/या यथासंभव निकटता से प्रभाव डालने पर जोर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय वह करने के लिए कह सकता है जो नहीं किया गया है। न्यायालय को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन उपायों के लिए प्रावधान किया गया है वे समाप्त हो गए हैं। जैसा कि श्री देसाई ने तर्क दिया है, यह सच है कि मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्थान के लिए नामित मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन साथ ही, समझौते द्वारा आवश्यक योग्यताओं और अन्य विचारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

13. "उचित सम्मान" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि कई परिस्थितियों पर उचित ध्यान केंद्रित किया गया है। एक सामान्य नियम के रूप में "आवश्यक" अभिव्यक्ति को मोटे तौर पर उन चीजों के रूप में कहा जा सकता है जिन्हें करना उचित रूप से आवश्यक है या कानूनी रूप से इच्छित कार्य की उपलब्धि के लिए सहायक है। आवश्यक उपायों को उनके द्वारा उठाए गए उचित कदमों के रूप में कहा जा सकता है।

14. ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय ने समझौते द्वारा आवश्यक योग्यताओं या एक स्वतंत्र और निष्पक्ष

मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य विचारों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मध्यस्थता समझौते में नामित मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन नियुक्ति करते समय धारा 11 की उप-धारा (8) की दोहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए और ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो नियुक्ति असुरक्षित हो जाती है। इन परिस्थितियों में, हम प्रत्येक मामले में की गई नियुक्ति को अलग करते हैं, ऊपर बताए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए नई नियुक्तियां करने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय को भेजते हैं।

बी. भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट में, तीन सेवारत अधिकारियों से मिलकर एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, लेकिन वास्तव में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके बाद, धारा 11 के तहत दायर एक आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने उस उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। निर्णय के पैराग्राफ 11 में उस प्रश्न को निर्धारित किया गया जो विचार के लिए उठा और पैराग्राफ 14 निम्नानुसार थाः -

" 14. उत्तर रेलवे के मामले में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्यस्थता समझौते के तहत प्रदान किए गए उपाय समाप्त हो गए हैं, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना

चाहिए कि अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (8) की दोहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। इसका मतलब यह होगा कि निश्चित रूप से न्यायालय को पहले मध्यस्थता समझौते में दिए गए तरीके से मध्यस्थों की नियुक्ति करनी चाहिए। लेकिन जहां मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में नियुक्त/नामित मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता संदेह में है, या जहां मध्यस्थता समझौते में प्रदान किए गए तरीके से नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने काम नहीं किया है और नई नियुक्ति करना आवश्यक हो जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित मध्यस्थता के प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए उचित वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए शक्तिहीन नहीं है। "

ग. उत्तर रेलवे प्रशासन (उपरोक्त) सहित इस मुद्दे पर मामलों पर विचार करने के बाद, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दियाः -

45. यदि मध्यस्थता समझौता किसी नामित मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान करता है, तो अदालतों को आम तौर पर मध्यस्थता समझौते के प्रावधानों को प्रभावी बनाना चाहिए। लेकिन जैसा कि उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है, जहां एक उचित आशंका पैदा करने के लिए सामग्री है कि मध्यस्थ के रूप में मध्यस्थता समझौते में उल्लिखित व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से या निष्पक्ष रूप से कार्य करने की संभावना नहीं है, या यदि नामित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति, विवाद को नामित मध्यस्थ को भेजने की सहमत प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारणों को दर्ज करने के बाद, अधिनियम की

धारा 11 (8) के अनुसार एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, विवादों को नामित मध्यस्थ को संदर्भित करना नियम होगा। मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश को केवल पक्षकारों को नामित मध्यस्थ या नामित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास भेजकर मध्यस्थता समझौते को दोहराना होगा। नामित मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण को नजरअंदाज करना और एक स्वतंत्र मध्यस्थ को नामित करना नियम का अपवाद होगा, जिसका उपयोग वैध कारणों से किया जाना चाहिए।

48. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मध्यस्थों की नियुक्ति की योजना वाले अधिनियम की धारा 11 के दायरे का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

(i) जहां समझौते में तीन मध्यस्थों (एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए प्रत्येक पक्ष और तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए दो नियुक्त मध्यस्थ) के साथ मध्यस्थता का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में जब कोई पक्ष दूसरे पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है (या दो नामित मध्यस्थ नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं), मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (4) के तहत शक्ति का प्रयोग करेगा।

(ii) जहां समझौते में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान है और पक्षकार किसी नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमत नहीं हैं, वहां मुख्य

न्यायाधीश या उनका नामित सदस्य धारा 11 की उप-धारा (5) के तहत शक्ति का प्रयोग करेगा, यदि पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर मध्यस्थता पर सहमत होने में विफल रहते हैं।

(iii) जहां मध्यस्थता समझौता नियुक्ति प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, तब चाहे मध्यस्थता एकल मध्यस्थ द्वारा हो या तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा, मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करेगा, यदि कोई पक्ष सहमत प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्य करने में विफल रहता है (या पक्ष या दो नियुक्त मध्यस्थ सहमत प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं या कोई व्यक्ति/संस्था उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहती है)।

(iv) जबकि 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करने में दूसरे पक्ष की विफलता उप-धारा (4) और (5) के तहत आने वाले मामलों में मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति से संपर्क करने के लिए मध्यस्थता की मांग करने वाले पक्ष को कार्रवाई का कारण प्रस्तुत करेगी, ऐसी समयबद्ध भर्ती धारा 11 की उप-धारा (6) में नहीं पाई जाती है। मध्यस्थता समझौते द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सहमत प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने में विफलता, या किसी निर्धारित समय-सीमा के अभाव में, उचित समय के भीतर, पीड़ित पक्ष को अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत याचिका दायर करने में सक्षम बनाएगी।

(v) जहां पक्षकारों के बीच नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमति हो गई है, लेकिन उप-धारा (6) के खंडों या (ग) के तहत मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की अधिकारिता को लागू करने के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, तो मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। उप-धारा (6) के तहत आवश्यक उपाय करने के लिए मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति से संपर्क करने की पूर्व शर्त यह है कि -

(i) एक पक्ष जो सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत आवश्यकता के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है; या

(ii) पक्षकार (या दो नियुक्त मध्यस्थ) सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं; या

(iii) एक व्यक्ति/संस्था जिसे सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कोई कार्य सौंपा गया है, जो ऐसा कार्य करने में विफल रहा है।

(vi) मुख्य न्यायाधीश या उसका नामित धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थता खंड में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास करेगा।

(vii) यदि परिस्थितियाँ मौजूद हैं, नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हैं, या यदि अन्य परिस्थितियाँ निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता होती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या उनका

नामित व्यक्ति, दर्ज किए जाने वाले कारणों से नामित मध्यस्थ की अनदेखी कर सकता है और किसी और को नियुक्त कर सकता है।

इस प्रकार, जैसा कि पैरा 48 के उप-पैरा (v) में निर्धारित किया गया है, जब तक कि 1996 अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत अधिकारिता का आह्वान करने के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं होता है, तब तक मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करने का कोई सवाल ही नहीं है।

डी. डेनेल (प्रोपराइटरी) लिमिटेड बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक अन्य मामले में, हालांकि मध्यस्थता समझौते में यह प्रावधान किया गया था कि सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रबंध निदेशक या उनके नामित व्यक्ति को भेजा जाए, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। निर्णय के पैरा 19 से 21 तक स्पष्ट कारण यह था कि मध्यस्थता का आह्वान करते समय अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से पारस्परिक रूप से सहमत स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था, लेकिन प्रत्यर्थी ने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। निर्णय का पैरा 20 उल्लेखनीय हैः -

"20. दातार स्विचगियर्स लिमिटेड बनाम टाटा फाइनेंस लिमिटेड मामले में इस न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की न्यायालय की शक्तियों पर विचार

करते हुए, भूपिंदर सिंह बिंद्रा बनाम भारतीय संघ मामले में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

"3. यह तय कानून है कि अदालत एक मध्यस्थ की नियुक्ति में हस्तक्षेप और हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जिसे पक्षों ने अनुबंध की शर्तों के तहत चुना है जब तक कि मध्यस्थ के कानूनी कदाचार, धोखाधड़ी, अयोग्यता आदि का अनुरोध और साबित नहीं किया जाता है। यह पक्षकार की अपनी इच्छा या खुशी से उसकी सहमति से नियुक्त मध्यस्थ के अधिकार को रद्द करने की शक्ति में नहीं है। रद्द करने के लिए उचित और पर्याप्त कारण होना चाहिए। "

उक्त सिद्धांत का सामान्य तरीके से पालन करना होगा।"

ई. इसी तरह, डेनेल (प्रोपराइटरी) लिमिटेड बनाम रक्षा मंत्रालय 'में, प्रासंगिक खंड महानिदेशक, आयुध कारखाना, भारत सरकार या उनके द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी के एकमात्र मध्यस्थता के लिए प्रदान किया गया है। यह देखा गया कि चूंकि निर्धारित अवधि के भीतर शासी खंड के संदर्भ में कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिवादी ने मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अधिकार खो दिया था। निर्णय के अनुच्छेद 21 और 24 इस प्रकार थेः -

"21. यह सच है कि सामान्य परिस्थितियों में धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय समझौते की शर्तों का यथासंभव बारीकी से पालन करेगा। लेकिन यदि परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के

नामित व्यक्ति को नामित मध्यस्थ के अलावा एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।"

24. यह भी याद रखना चाहिए कि धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय भी न्यायालय को अधिनियम की धारा 11 (8) में निहित प्रावधानों का उचित सम्मान करना आवश्यक है। उपरोक्त धारा में यह प्रावधान है कि यह सुनिश्चित करने के अलावा कि मध्यस्थ के पास पक्षों के समझौते द्वारा मध्यस्थ के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं, न्यायालय को अन्य विचारों को ध्यान में रखना होगा जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने की संभावना रखते हैं। उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि आम तौर पर न्यायालय सहमत प्रक्रिया के संदर्भ में नियुक्ति करेगा, यह मत व्यक्त किया है कि मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति इसके कारण दर्ज करने के बाद इससे विचलित हो सकता है।

एफ. भारत संघ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड में, वर्ष 2007 में तीन राजपत्रित रेलवे अधिकारियों से युक्त एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया था और चार साल पारित होने के बावजूद मामला समाप्त नहीं हो रहा था। इन परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार करने की याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया था।

इस शिकायत पर विचार करते हुए कि ऐसी नियुक्ति संबंधित मध्यस्थता खंड से परे थी, इस न्यायालय ने कहाः -

"12. जैसा कि धारा 14 के पढ़ने से स्पष्ट है, जब मध्यस्थता न्यायाधिकरण की ओर से कार्य करने में विफलता होती है और वह न्यायिक या वास्तविक रूप से अपना कार्य करने में असमर्थ होता है, तो मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक पक्ष के लिए आदेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला होता है। धारा 15 कुछ और आकस्मिकताओं का प्रावधान करती है जब मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो सकता है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय एक स्पष्ट निष्कर्ष पर आया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपना कार्य करने में विफल रहा है और यह सही है। यह न्यायाधिकरण के सदस्यों की ओर से मामले में आगे बढ़ने में असमर्थता का एक स्पष्ट मामला है क्योंकि मामला लगभग चार साल तक बिना किसी तुकबंदी या उचित कारणों के चला। सदस्यों ने तब भी अपना रास्ता नहीं बदला जब उन्हें तीन महीने का समय देकर एक और जीवन दिया गया। वस्तुतः उच्च न्यायालय द्वारा एक आकस्मिक आदेश पारित किया गया था, लेकिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण अप्रभावित रहा और उसने उच्च न्यायालय के निर्देशों को बेपरवाह तरीके से लिया। इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश को समाप्त करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश त्रुटिहीन है। वर्तमान अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी द्वारा विवादित आदेश के इस पहलू पर सवाल भी नहीं उठाया जाता है। हालाँकि, अपीलार्थी का तर्क है कि भले ही यह अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार

था, वैकल्पिक मध्यस्थों को "उन नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाना चाहिए था जो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लागू थे।" इस आधार पर, यह श्री मेहता, विद्वान ए. एस. जी. का निवेदन था कि उच्च न्यायालय को जी. सी. सी. के खंड 64 में निहित प्रावधान का सहारा लेना चाहिए था।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम तौर पर यही स्थिति होगी। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय सभी मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की कार्रवाई को अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए या क्या जोड़ों में खेलने की गुंजाइश है और उच्च न्यायालय को कुछ परिस्थितियों में विवेकाधिकार का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जाता है? यदि हाँ, तो वे परिस्थितियाँ क्या हैं? यह वही पहलू है जिस पर इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से ट्रिपल एंग में विचार किया गया था। काम करता है। विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने बताया कि यह धारणा कि उच्च न्यायालय पक्षों के बीच अनुबंध के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए बाध्य था, हाल के दिनों में एक महत्वपूर्ण क्षरण देखा गया है। उक्त निर्णय के पैरा 6 और 7 में उन निर्णयों पर ध्यान दिया गया है जिनमें उपरोक्त "शास्त्रीय धारणा" से विचलन किया गया है।

जी. वॉइस्टाल्पाइन शियेनन जी. एम. बी. एच. बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड "में, प्रासंगिक खंड में विचार किया गया कि विवादों का निपटारा प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई पांच इंजीनियरों की सूची में से तीन मध्यस्थों द्वारा किया जाए। अपीलार्थी ने ए. सी.

टी. में संशोधन के बाद 14.06.2016 पर मध्यस्थता का आह्वान किया था। जब उत्तरदाताओं द्वारा सेवारत अधिकारियों सहित पांच व्यक्तियों की सूची प्रदान की गई थी, तो एक आपत्ति जताई गई थी कि इस तरह की प्रक्रिया से अधिनियम की अनुसूची 7 के खंड 1 के साथ पठित धारा 12 (5) को देखते हुए "अवैध व्यक्तियों" की नियुक्ति होगी। इस न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 12 को विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया था, जो विशेष रूप से "मध्यस्थों की तटस्थता" के मुद्दे से निपटता है, और कहा कि यदि मध्यस्थता खंड संशोधित प्रावधानों के साथ गड़बड़ पाता है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति, भले ही स्पष्ट रूप से समझौते में मध्यस्थता खंड के अनुरूप हो, अवैध होगी और इस प्रकार न्यायालय ऐसे मध्यस्थ (ओं) को नियुक्त करने के लिए अपनी शक्तियों के भीतर होगा जो अनुमेय हो। पैराग्राफ 18 मामले के इस पहलू का सारांश देता हैः -

"18. विधि आयोग की पूर्व-उद्धृत सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, जिसके साथ धारा 12 को संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, यह स्पष्ट है कि प्रावधान में संशोधन का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों की तटस्थता का प्रावधान करना था। इसे प्राप्त करने के लिए, धारा 12 की उप-धारा (5) में कहा गया है कि इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकारों या वकील या विवाद के विषय के साथ संबंध सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। ऐसी स्थिति में जब

मध्यस्थता खंड को ऊपर निकाले गए संशोधित प्रावधानों के साथ गड़बड़ी मिलती है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर होगी, जिससे अदालत को ऐसे मध्यस्थ (ओं) की नियुक्ति करने का अधिकार होगा जो अनुमेय हो। यह धारा 12 की उप-धारा (5) में निहित अबाधित खंड का प्रभाव होगा और दूसरा पक्ष मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति पर जोर नहीं दे सकता है।"

21. ऊपर निर्दिष्ट वोएस्टाल्पाइन शियेनन जी. एम. बी. एच. (ऊपर उल्लिखित) में इस न्यायालय के निर्णय को छोड़कर, अन्य सभी निर्णय उन मामलों से उत्पन्न हुए जहां संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले मध्यस्थता का आह्वान किया गया था। वोएस्टाल्पाइन शियेनन जी. एम. बी. एच. (ऊपर दिया गया) एक ऐसा मामला था जहां संशोधन अधिनियम के बाद अनुरोध 14.6.2016 पर था और पैरा 18 में टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चूंकि "मध्यस्थता खंड संशोधित प्रावधानों में गड़बड़ी पाता है", इसलिए न्यायालय को ऐसे मध्यस्थ (ओं) को नियुक्त करने का अधिकार था जो अनुमेय हो। मध्यस्थ की अयोग्यता उस मामले में सातवीं अनुसूची (जिसे संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था) के साथ पठित संशोधित धारा 12 के संदर्भ में पाई गई थी, जहां मध्यस्थता का आह्वान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूर्व-संशोधन मामलों में, उत्तर रेलवे प्रशासन (सुप्रा) में निर्धारित कानून, जैसा कि उपरोक्त सभी मामलों में पालन किया जाता है, लागू किया जाना चाहिए, जिसमें समझौते की शर्तों का पालन किया जाना चाहिए और/या यथासंभव निकटता से प्रभाव डाला जाना चाहिए। इसके अलावा, 1996 अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय की अधिकारिता केवल तभी उत्पन्न होगी जब खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाएं। ऊपर निर्दिष्ट मामलों से पता चलता है कि एक बार

धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की शर्तें धारा 11 (8) के तहत परिणामी शक्ति के प्रयोग में संतुष्ट हो गईं, तो न्यायालय ने कुछ अवसरों पर संबंधित मध्यस्थता खंडों के दायरे से परे जाकर स्वतंत्र मध्यस्थों को नियुक्त किया था। स्पष्ट है कि धारा 11 (8) के तहत ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए पहले धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए मामला बनाया जाना चाहिए।

22. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से जो सिद्धांत उभरते हैं वे हैंः -

ए. 1996 अधिनियम द्वारा शासित सभी मामले, जो संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले थेः -

(i) यह तथ्य कि नामित मध्यस्थ किसी एक पक्ष का कर्मचारी है, वास्तव में उसकी ओर से पक्षपात या पक्षपात या स्वतंत्रता की कमी का अनुमान लगाने का आधार नहीं है। तथापि, एक कर्मचारी मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में एक न्यायोचित आशंका हो सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति विषय अनुबंध के संबंध में नियंत्रण या व्यवहार करने वाला प्राधिकारी था या यदि वह उस अधिकारी के सीधे अधीनस्थ है जिसका निर्णय विवाद का विषय है।

(ii) जब तक 1996 के अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत अधिकारिता लागू करने के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं होता है, तब तक मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करने का कोई सवाल ही नहीं है।

(iii) मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय मध्यस्थता खंड में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे। .

(iv) धारा 11 की उप धारा (6) के तहत ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय, यदि परिस्थितियां मौजूद हैं, जो नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हैं, या यदि अन्य परिस्थितियां निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गारंटी देती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित, दर्ज किए जाने वाले कारणों से नामित मध्यस्थ की अनदेखी कर सकता है और किसी और को नियुक्त कर सकता है।

बी. संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद 1996 अधिनियम द्वारा शासित मामलों मेंः

-

यदि मध्यस्थता खंड को संशोधित प्रावधानों में गड़बड़ी मिलती है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति, भले ही स्पष्ट रूप से समझौते में मध्यस्थता खंड के अनुरूप हो, अवैध होगी और इस प्रकार न्यायालय ऐसे मध्यस्थ (ओं) को नियुक्त करने की अपनी शक्तियों के भीतर होगा जो अनुमेय हो।

23. जैसा कि ऊपर उद्धृत अनुच्छेद 1 में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से पता चलता है कि यह अभ्यास उच्च न्यायालय द्वारा "तटस्थता बनाने या याचिकाकर्ता के मन में संदेह से बचने के लिए" किया गया था और यह सुनिश्चित किया गया था कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए और किया जाता हुआ भी देखा जाना चाहिए। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने तटस्थता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को लागू किया, जिन्हें संशोधन अधिनियम के माध्यम से विस्तारित किया गया है, तब भी जब धारा 11 (6) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ था। अपरिवर्तित धारा 12 में निर्धारित प्रक्रिया में मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करने की संभावना वाली परिस्थितियों का प्रकटीकरण अनिवार्य है। प्रत्यर्थी का यह मामला नहीं है कि धारा 12 के प्रावधानों का बिना

संशोधन के किसी भी रूप में उल्लंघन किया गया है। किसी भी मामले में प्रावधान में स्पष्ट और सटीक प्रक्रिया पर विचार किया गया जिसके तहत मध्यस्थ को चुनौती दी जा सकती है और धारा 13 के तहत उस ओर से आपत्तियों को निर्धारित समय के भीतर और उसमें विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार उठाया जा सकता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि समय के भीतर और निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में ऐसी कोई चुनौती नहीं उठाई गई थी। वास्तव में, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता में भाग लिया था और अपने दिनांक 04.12.2015 के संचार द्वारा, अपने दावे का बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी।

24. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी और उसे मध्यस्थता की प्रक्रिया और प्रगति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इसलिए हम अपीलार्थी द्वारा उठाई गई चुनौती को स्वीकार करते हैं और प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई चुनौती को अस्वीकार करते हैं। नतीजतन, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 25206-25207/2016 से उत्पन्न होने वाली अपीलों की अनुमति दी जाती है, जबकि विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 503-504/2017 से उत्पन्न होने वाली अपीलें खारिज कर दी जाती हैं। मध्यस्थता, 19.08.2015 पर मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुसरण में, कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।

25. अपील का निपटान उपरोक्त शर्तों में, लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना किया जाता है।

अपील निस्तारित की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक हेमंत सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।